works which shall not be allowed under the scheme. The guidelines have been circulated to the Hon'ble MPs.

(b) An amount of Rs. 1 Crore for each MP is proposed to be allocated during 1995-96 financial year.

(c) The total money is to be released in two instalments.

दालों की खपत, आपूर्ति, उत्पादन और आयात

72. **श्री अनन्तराम जायसवाल** :

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दालों की वार्षिक खपत तथा आपूर्ति का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष में दालों की खपत के लिए खपत के हिसाब से उनका उत्पादन कितना हैं;

(ख) क्या यह सच हैं कि सरकार ने दालों का आयात करने का निर्णय लिया हैं; यदि हां, तो दालों के आयात के क्या कारण हैं और किस आधार पर तथा कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार जनहित में यह सुनिश्चित करेगी कि दालों का आयात करने से घरेलू बाजार में उनके मूल्य विदेशी बाजारों मे उनके मूल्यों के समतुल्य रहें?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) दालों के उत्पादन के आधार पर दालों की मांग और आपूर्ति के बीच लगभग 4 मिलियन मीटरी टन का अन्तर होता है। उत्पादन स्तर पर लगभग 16-17 मिलियन मीटरी टन की वर्तमान आवश्यकता के प्रति फसल वर्ष 1989-90 से 1993-94 (जुलाई – जून) की अवधि के दौरान दालों का वास्तविक उत्पादन 12 से 13 मिलियन मीटरी टन के बीच हुआ हैं। फसल वर्ष 1994-95 के दौरान संभावित उत्पादन 14.33 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है। समस्त उत्पादन मे से बीज, पशुचारा और बर्बादी के प्रयोजन की मात्रा को घटाकर दालों की शेष मात्रा का जनता द्वारा उपयोग कर लिया जाता है।

(ख) और (ग) उत्पादन स्तर पर दालों के लगभग 4 मिलियन मीटरी टन के अन्तर के प्रति पिछले कुल वर्षो के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस पर दालों का वार्षिक आयात 4 से 6 लाख मीटरी टन के बीच हुआ हैं, जो मांग की आपूर्ति के बीच व्यापक अन्तर की तुलना में सार्थक नहीं हैं। अत: इस आयात से दालों के घरेलू मूल्यों पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि,

आयात में और वृद्वि करने की दृष्टि में आयात के लिए दालों को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखा गया हैं और सरकार ने हाल ही मे दालों पर सीमा-शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

Resource shortfall in mid-term appraisal of the Eighth Plan

73. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the resource shortfall estimated by mid-term appraisal of the Eighth Plan;

(b) how the outlay target for the current year is proposed to be met; and

(c) the impact of shortfall in various sectors?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) Necessary exercise partaining to Mid-Term Appraisal (MTA) of the Eighth Five Year Plan (1992—97) is underway in the Planning Commission in consultation with the concerned Ministries/Departments of Government of India.

(b) The outlay for Annual Plan 1995-96 is proposed to be financed through different sources of finance such as budgetary support. Internal and extra budgetary resources of public enterprises, borrowings including small savings and provident funds, external aid etc. as per the approved scheme of Financing of public sector plan.

(c) The question of shortfall, if any, will arise only after the mid-term appraisal is finalised.